molasses were regulated has been rescinded on 10th June, 1993 with a view to remove controls on prices and distribution of molasses. After decontrol, the production and requirement of molasses is not being monitored by the Government.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए मापदंड

1245. **श्री गोविन्द राम मिरी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संगठन के नये क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये हैं या दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में ग्वालियर में नये क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना करते समय उपर्युक्त मानदंडों या निर्देशों का अनुपालन किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में कोई मानदण्ड अथवा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों की पर्याप्त संख्या, मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विद्यालयों के बीच परिवहन तथा संचार संबंधी सुविधाओं, विद्यालयों का प्रभावी शैक्षिक तथा प्रशासनिक निरीक्षण करने की जरूरत तथा लागत प्रभावशीलता सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के पश्चात इसके शासी बोर्ड के निर्णय के आधार पर ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने दिनांक 18 अक्तूबर, 1995 को हुई अपनी 60वीं बैठक में ग्वालियर में 19वां क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ताकि ग्वालियर के आस-पास स्थित केन्द्रीय विद्यालयों का शैक्षिक तथा प्रशासनिक निरीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा सके।

Soil Erosion in Uttar Pradesh

1246. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey on the land affected by soil erosion in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat;

(b) if so, when was the last assessment made;

(c) the approximate land affected by soil erosion, sand dune and water logging in those States including river erosion;

(d) the measures taken by the Centre to save the land from erosion; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) The assessment of the land affected by soil erosion in the country has been documented in the Report of the Working Group for Planning Based on Land and Water Use for the formulation of V of VIII Five Year Plan (submitted in June, 1989).

(c) The estimated land affected by soil erosion (water erosion) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat are 58.98 lakh ha., 155.10 lakh ha. and 94.62 lakh ha. and due to water logging 19.80 lakh ha. 0.57 lakh ha. and 4.84 lakh ha. respectively. In addition, an area of 7.04 lakh ha. land is affected by wind erosion (sand dunes) in Gujarat State.

(d) and (e) Following are some of the important Soil Conservation Programmes undertaken by Government of India to save the land from erosion: